वह बहुत कम है। जो सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है, उससे ज्यादा तो एक क्विंटल पर किसान का खर्च होता है।

प्रश्न यह कि प्रथम तो सिन्थैटिक यार्न का आयात बन्द होना चाहिये, दूसरे हमारे देश का कपड़ा हमारे देश के मिलों में प्योर कोटन का बनाया जाना चाहिये और अगर सिन्थैटिक यार्न का कपड़ा हमारे देश के मिलों में बने तो कोटन का एक्सपोर्ट खुले रूप से होना चाहिये ताकि किसान की कोटन का मूल्य बढ़ सके और किसान का घर पूरा हो सके।

मगर आज जो सिन्थैटिक यार्न का आयात किया जा रहा है और कोटन का निर्यात बन्द किया जा रहा है, यह किसान विरोधी है और मिल मालिकों के साथ भारी पक्षपात है। यह नीति कृषि प्रधान देश में अपनाई जानी उचित नहीं है। अतः केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि किसान को लाभ पहुंचाने और कोटन उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिये कोटन का निर्यात खुले रूप से किया जाना चाहिये और कोटन बाहर से मंगाई जाने में पूरी तरह से रोक लगाई जाय, जैसे गत वर्ष पाकिस्तान से मंगाई गई थी, और दूसरे सिन्टिथैक यार्न के आयात पर भी पाबन्दी लगाई जानी चाहिये।

(viii) IMPENDING STRIKE BY TEXTILE WORKERS OF TAMIL NADU AND PONDICHERRY.

SHRI ERA MOHAN (Coimbatore): All the textile unions of Tamil Nadu and Pondicherry have given a joint call for indefinite strike from 11-11-82 onwards in all the 130-odd mills involving more than 2 lakh workers. In Coimbatore city alone there are 103 textile mills employing more than 1 lakh workers. The textile workers were getting so far higher bonus than the statutory minimum of 8.33 per cent under the S.I.M.A. formula arrived at unanimously between the managements and all trade unions. Now, under communication F. No. 204/21/80-IT A. II dated 4-12-80, the Central Board of Direct Taxes has declared that any amount paid as bonus in excess of 8.33 per cent statutory minimum is subjected to income-tax. This has become a convenient handle for the managements to declare only the statutory minimum bonus of 8.33 per cent.

If the textile workers of Tamil Nadu and Pondicherry are not prevented from going on strike, from 11-11-82, there will definitely be serious loss in production which may not be able to be recovered even in a decade.

The textile workers of Tamil Nadu and Pondicherry must be enabled to get bonus under S.I.M.A. formula which is an improvement over the Bonus Act, Formula by directing the Central Board of Direct Taxes to rescind the order in question and all the profit-making organisations should not be subjected to income-tax for paying higher bonus than 8.33 per cent.

(ix) RESERVATION FACILITY AT PATNA JUNCTION.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, पटना बिहार की राजधानी है। वहां से प्रत्येक दिन हजारों यात्री राज्य और देश के सुदूर स्थानों तक यात्रा करते हैं। यात्रियों को सुविधा के लिये वर्षों से पटना जंक्शन पर आरक्षण की व्यवस्था है। इसके लिये वहां बाजाप्ता कार्यालय खुला हुआ है। सभी गाड़ियों में आरक्षण के लिये वहां भीड़ लगी रहती है। भारी भीड़ को देखते हुये वहां आरक्षण की सुविधा और बढ़ाने की आवश्यकता है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि रेलवे प्रशासन वहां से दैनिक आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पटना जंक्शन की स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय हो जायेगी।